

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री श्रीचन्द्र गोयल : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We come to Bills to be taken up for general discussion. Shri K. R. Ganesh, absent. Shri Narayana Reddy, absent. Shri Yamuna Prasad Mandal, absent. Shri Madhu Limaye.

18.23 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Omission of Article 314)

by Shri Madhu Limaye

श्री मधु लिमये (मुंजर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान की धारा 314 को संविधान से हटाने वाले मेरे विधेयक पर यह सदन विचार करे।.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration".

You may continue next time. Now, the Home Minister.

18.24 hrs.

STATEMENT RE-PROROGATION OF BOTH HOUSES OF JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Deputy

Speaker, Sir, Government have received reports that the Governor of Jammu and Kashmir has prorogued both the Houses of the Jammu and Kashmir Legislature with effect from 8-00 A. M. tomorrow, the 14th March, 1970. It has been stated in a press note reported to have been issued by the Jammu and Kashmir Government that the order of prorogation has been necessitated on account of the agitation launched in Jammu by various groups and parties which has seriously affected the proceedings of the current session of the Legislature.

श्री मधु लिमये (मुंजर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : On a point of order, Sir. You Cannot ask a Question on a statement made by a Minister. Nor can you ask a clarification.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : You are 10 years behind.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने काश्मीर सरकार के द्वारा जो प्रेस विज्ञापित प्रकाशित की गई, है उस का सारांश ही सदन को बताया है, जिसमें एक बहुत गम्भीर बात उन्होंने बताई है कि चूँकि जो आन्दोलन वहाँ चल रहा है, उस आन्दोलन की वजह से विधान सभा का कार्य नहीं चल पा सकता है, इस लिये विधान सभा का सत्रावसान किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई भी सरकार यह वक्तव्य दे कि किसी आन्दोलन के कारण विधान सभा का काम नहीं चल सकता है, तो उसका साफ मतलब है कि कानून और संविधान उस राज्य में खतम हो चुका है। ऐसी स्थिति में संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति का मतलब है केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वहाँ का शासन अपने हाथ में ले। इस में कहा गया है —

"If the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise"....

प्रदरवाईज पर ध्यान दीजिये, यदि मन्वर रिपोर्ट न दे और आपकी अपनी जानकारी हो तो भी